

प्रेषक,

डीएससो गर्वाल,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

शहरी विकास निदेशालय,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुसार-2

देहरादून: दिनांक 23 मई, 2016

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगरपालिका परिषद, गौचर को अवस्थापना विकास निधि से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, गौचर के पत्राक-165/मुख्यमंत्री-प्रमाण/(दिनांक 14.05.2016)/अवस्थापना निधि, दिनांक 17.05.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरपालिका परिषद, गौचर द्वारा निकाय क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तुत सलग्नक-1 में उल्लिखित विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु कार्यवार संस्तुत कुल ₹ 11.00 लाख (रुपये ग्यारह लाख मात्र) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन में रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

1. उक्त धनराशि कुल ₹ 11.00 लाख (रुपये ग्यारह लाख मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगरपालिका परिषद, गौचर को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
3. स्वीकृत कार्य करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्यियता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
4. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुलय कराये जायेंगे।
5. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
6. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं योजनाओं/कार्यों पर किया जायेगा, जिस हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
8. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपर्युक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
9. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
10. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
11. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराए जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

12. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोप में जमा करा दी जाय।
13. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुस्थान की शर्त में रखी जायेगी।
14. धनराशि का दिनांक 31-3-2017 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2— उक्त के सबध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान स0-13 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनापत्र- 181-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास-20 सहायक अनुदान/अशादान/राज सहायता के नाम डाला जाएगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/xxvii(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलोटमेन्ट आई डी-5/605/30269 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डीएस० गर्वाल)  
सचिव।

स0-8/4 (1) / IV(2)-श0वि0-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) / महालेखाकार (आइटी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मारू मुख्यमंत्री जी / शहरी विकास मंत्री जी।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी।
4. जिलाधिकारी, चमोली।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एनोआईसी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी०आ० में इसे शामिल करें।
9. अधिकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, गौचर।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

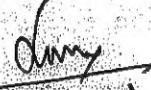
(डीएस० राणा)  
उप सचिव।

शासनादेश संख्या: 814 / IV(2)-श0वि0-2016-90(सा0)14, दिनांक 23 मई, 2016 का संलग्नक।

(धनराशि ८ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	स्वीकृत धनराशि
1.	वार्ड नं0 01 में सी0सी0 नाली, सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	3.00
2.	वार्ड नं0 02 में सी0सी0 नाली, सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	2.00
3.	वार्ड नं0 03 में घली बैन्ड समीप कालोनी में सी0सी0 नाली, सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	3.00
4.	वार्ड नं0 04 में धूप छांव कालोनी में सी0सी0 नाली, सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	3.00
योग—		11.00

(जप्ये ग्यारह लाख मात्र)

  
(डी0एन0एस0 राणा)  
उप सचिव।

